ग्रीन रिवोल्ट

हरित-नीरा रहे वसुंधरा

पेजः 4

सूरज से निकलेगा तरक्की का रास्ता

रविवारीय, 20 - 26 अक्टूबर 2019, वर्ष- एक, अंक-11, रांची | हिन्दी साप्ताहिक | R.N.I. No. JHAHIN 00962 | कुल पृष्ठ 4 | मूल्य 2 रूपये

सूचना

ग्रीन रिवोल्ट के पाठकों से आग्रह है कि आप पर्यावरण, कृषि, जल संरक्षण, पशुपालन, बागवानी , पेट्स, वृक्षारोपण से संबंधित खबरें, समस्यायें, लेख,सुझाव, प्रतिक्रियायें या तस्वीरें हमें अवश्य भेजें। हमारा इमेल एवं ह्वाट्सएप नंबर है।

greenrevolt2019@gmail.com

9798166006

डीवीसी की बेरमो माइंस सीसीएल को हस्तांतरित

रांची :झारखंड के बोकारो जिले में स्थित दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) की बेरमो खदान को सीसीएल को मुख्य अतिथि सीएमडी सीसीएल गोपाल सिंह, माननीय पूर्व सांसद रविंद्र पांडेय, डीवीसी के मेंबर सेक्रेट्री पी के मुखोपाध्याय की उपस्थिति में हस्तांतरित किया गया। यह हंस्तांतरण संबंधित मंत्रालयों के मार्गदर्शन में सीसीएल और डीवीसी प्रबंधन के दो वर्षों के निरंतर प्रयासों के बाद हुआ है। डीवीसी की इस खदान में वर्ष 2017 से उत्पादन विभिन्न तकनीकी कारणों, संसाधनों एवं मंजूरियों के अभाव के चलते बंद था ।

19 महिलाओं को मिला मिट्टी की डॉक्टर का मिला प्रशिक्षण

मेदिनीनगर, प्रतिनिधिः राज्य सरकार ने किसानों की समृद्धि के लिए जहां एक ओर मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना से किसानों को लाभान्वित कर रही है। वहीं दूसरी ओर उनके खेतों की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए मिट्टी की ।डॉक्टर की नियुक्ति प्रक्रिया राज्य भर में हो रही है। इसी के तहत पलामू के मेदिनीनगर और चैनपुर प्रखंड की सखी मंडल की 19 महिलाओं को मिट्टी की डॉक्टर का आठ दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हजारीबाग में संपन्न कराया गया। उम्मीद है प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षण प्राप्त महिलाएं अपने क्षेत्र में किसानों को उचित सलाह देते हुए उनके खेत की उत्पादकता को बढ़ाने में सहायक होंगी। ये बातें सचिव कृषि श्रीमती पूजा सिंघल ने कही।

मिट्टी को बनाएंगी स्वस्थ, उत्पादकता से लाभान्वित होंगे किसान

सचिव कृषि श्रीमती पूजा सिंघल ने बताया कि मेदनीनगर प्रखंड से आठ और चैनपुर प्रखंड से 11 सखी मंडल की महिलाओं को उक्त प्रशिक्षण हजारीबाग के डेमोटांड़ स्थित प्रशिक्षण केंद्र में दिया गया है। इन महिलाओं को मिट्टी जांच हेतु किट भी प्रदान किया गया। अब महिलाएं अपने पंचायत के प्रत्येक किसान की खेत की मिट्टी लेकर उसका जांच करेंगी एवं सॉइल हेल्थ कार्ड में दिए गए सुझाव एवं पोषक तत्वों की पूर्ति हेतु सुझाए गए उर्वरकों की मात्रा के विषय में सभी किसानों को अवगत कराएंगी।

दीपावली में रांची में तकरीबन सवा दो करोड़ की मिठाइयां बिकती हैं वहीं मिलावट के मामले में बड़े और प्रतिष्ठित दूकानदार भी शामिल रहते हैं

मिठाइयों में मिलावट का बाजार

वरीय संवाददाता

रांची : पर्व त्यौहारों में दीपावली सबसे ज्यादा रौनक वाला त्यौहार है। घर की साफ सफाई रंग रोगन के बाद रोशनी और धूम धड़ाके के बाद पूजन और तरह तरह की मिठाइयों का लुत्फ। इस दिन मिठाइयों का विशेष महत्व है और उपहार स्वरूप इसे लेने देने की परंपरा भी। दीपावली के दिन आम दिनों की तरह हम एक नही बल्कि कई प्रकार की मिठाइयों की खरीददारी करते हैं। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ रांची में ही तकरीबन ढाई करोड़ की मिठाइयों का कारोबार होगा। लेकिन इस खुशी के रंग में भंग करने के लिये मिलावटखोरों की भी फौज तैयार रहती है। छोटे मोटे मिलावटखोर दूकानदारों की बात हम छोड़ भी दें तो प्रतिष्ठित और बड़े दूकानदार भी दीपावली के बाजार में हाथ साफ कर लेते हैं। दीपावली का बाजार इन मिलावटखोरों के लिये अवैध धंधे का मौका भी मुहैया करा देता है। लेकिन इन सबका नतीजा आम जन को भुगतना पड़ता है।

मिठाइयों में मिलावट को अंग्रेजी में sweet Adulteration कहते हैं।आजकल मिठाइयों में मिलावट की आशंका के चलते ड्राई फ्रूट लेन-देन चलन में है। लेकिन फिर भी घर में मिठाई तो आती ही है, और मधुमेह के मरीज भी इस दिन परहेज करते करते मिठाई खा जाते हैं। तो मिठाई की खरीददारी समझदारी से करें।

अस्थायी दूकानदारों पर भरोस न करें

मिठाइयों का बड़ा बाजार देख कर सिर्फ दीपावली में कुछ व्यवसायी मिठाई की दूकान लगाते हैं। चुंकि ऐसे दूकानदारों को सालो भर मिठाई नहीं बेचनी होती इस कारण से ये किसी भी तरह की मिलावटी मिठाइयां एक दिन बेच कर चल देते हैं? मिठाई हमेंशा किसी प्रतिष्ठित और बड़े दूकान से ही खरीदें। क्योंकि ऐसे दूकानदारों को अपने ब्रांड वैल्यू की भी चिंता रहती है।

किसमें क्या मिलावट होती है?

मिलावट डायरेक्ट मिठाई में नहीं, बल्कि जिस चीज़ में मिठाई बनती है। उसमें की जाती है। जैसे :

●वर्क में एल्यूमिनियम मिलाया जाता है।●दूध में पानी/यूरिया/रंग/वांशिग पाउडर मिलाया जाता है। ●घी में चर्बी मिलाया जाता है।●मेवे में अरारोट, चीनी मिलाया जाता है।●खोये में आटा, मैदा मिलाया जाता है।●क्रीम मिठाइयों में नकली क्रीम की परत होती है

मिलावटखोरों के प्रति सरकारी रवैया नरम

खाने की चीजों में मिलावट के लिए अपमिश्रण अधिनियम 1954 में बना था। इसके अन्तर्गत मिलावट करने वाले को पकड़े जाने पर 6 महीने की जेल हो सकती है। हालांकि इस कानून का भय मिलावटखोरों में न के बराबर दिखता है। दूसरी बात कि, दिपावली में मिलावटी मिठाइयों की शिकायत पर खाद्य नियामक टीम मिठाइयों को लैब में मिलावट की जांच के लिये भेजती है जिसकी रिपोर्ट दो सप्ताह में आती है। तब तक जिसका जितना नुकासान होना होता है वो हो चुका होता है और मामला पुराना होने से कार्रवाई के बजाय लीपापोती हो जाती है।

सावधानी के लिये आप पहले से पैक मिठाइयां न लें, मिल्क केक तथा, क्रीम वाली मिठाइयों से परहेज करें, परिचीत दूकानदार से ही मिठाइयां लें।

थोड़ी सावधानी बरते और मिठाई जरूर खायें

भारत में मिठाइयों के बारें में बहुत सारी बातें कही गयी हैं? और कुछ मिठाइयों का उल्लेख तो हमारे पौराणिक ग्रंथों तक में मिलता है। रसगुल्ले जैसी मिठाई के आविष्कार और अधिकार को लेकर उड़ीसा और बंगाल के बीच तो कानूनी लड़ाई तक बात पहुंच गयी थी।

पाक कला के कुछ जानकारों ने कहा है कि , मनुष्य को अपने जीवन काल में कुल नौ प्रकार की मिठाइयों का स्वाद अवश्य लेना चाहिये। उसमें रसगुल्ले और काशी की मलाई गिलौरी मिठाई का नाम आता है।

जानकार बताते हैं कि, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने चॉकलेट जैसे उत्पादों की सेल बढाने के लिये भी मिलावट की खबर को खूब उछाला ताकि हम भारतीय डर कर चॉकलेट, चिप्स वेफर खरीदें, लेकिन थोड़ी सी सावधानी बरत कर हम मिठाई खरीदें तो आराम से इसका लुत्फ ले सकते हैं और दीपावली का आनंद दुगुना कर सकते हैं।

मिलावट के कुछ खास तथ्य

●मिठाई हाथ में लेने पर, हाथ में रंग लग जाता है तो खतरनाक है मिठाई में रंग लाने के लिए सबसे ज्यादा मेटानिल येलो और टारट्राजाइन मिलाया जाता है। इससे किडनी डेमेज का खतरा बढ़ जाता है। ●मेवे में मिलावट की पहचान के लिए फिल्टर पर आयोडीन की दो बूंद डालें। इसका काला पड़ना बताता है कि इसमें मिलावट है।● खोया दानेदार हो तो भी मिलावटी हो सकता है।● मिठाई पर लगा वर्क असली होगा तो जलाने पर छोटी गोलीनुमा आकृति में बन जाएगा। नकली होगा तो स्लेटी रंग का जला हुआ कागज का दिखेगा●नकली केसर पानी में डालने के बाद रंग छोड़ने लगता है। असली केसर पानी में कोई रंग नहीं छोड़ता।●ज्यादा रंगीन मिठाइयों को खरीदने से बचें।

जनता जगी रहती है तो सरकार बेहतर काम करती है:रघुवर दास

लिट्टीपाड़ाः प्रतिनिधि

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने लिट्टीपाड़ा स्थित नावाडीह मैदान में जन चौपाल में लोगों को संबोधित करतक हुये कहा कि जन चौपाल के माध्यम से मैं आप सबों को जगाने आया हूं। लोकतंत्र के मूल मंत्रों में जागरण शामिल है। जब तक हम जागते रहते हैं तो घर में चोर- चोरी नहीं करता। इसी तरह अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जगी रहती है तो सरकार बेहतर काम करती है। जनता जितना जागरूक होगी। सरकार द्वारा संचालित योजनाएं उतनी सफल होंगी। मेरे लिए लिट्टीपाड़ा प्रखंड महत्वपूर्ण रहा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद से संथाल परगना और लिट्टीपाड़ा के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहा हूं। सरकार बनने के बाद जब मैं पहली बार लिट्टीपाड़ा में आयोजित जन चौपाल में आया था। तब यहां की पहाड़िया बहनों ने पेयजल की संकट से उबारने को कहा था। मैंने 217 करोड़ की पेयजल योजना शुरू कराया। योजना अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। जल्द लोगों के घरों तक पाइपलाइन से शुद्ध पानी उपलब्ध होगा।

लिट्टीपाड़ा को विकसित करना सरकार का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि लिट्टीपाड़ा प्रखंड सबसे पिछड़ा प्रखंड है। सरकार का लक्ष्य लिट्टीपाड़ा को विकसित प्रखंडों की श्रेणी में लाना है। मुख्यमंत्री बनने के बाद से मैं लगातार आम जनों से सीधा संवाद स्थापित करता हूं। ताकि कहीं कोई परेशानी हो तो उसका समाधान किया जा सके। आम लोगों के लिए योजना तैयार किया जा सके। अपने कार्यकाल में योजना बनाओ अभियान, जन चौपाल के माध्यम से राज्य की जनता से मैंने सीधा संवाद किया है। उनकी सोच के अनुरूप योजना तैयार हुई। ताकि राज्य से गरीबी दूर हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने किसानों की समस्या को समझा। अब किसान केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एवं राज्य सरकार की मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना से लाभान्वित हो रहे हैं।

मेदिनीनगर में महिलाओं ने व्यावसायिक तरीके से की मुनगे की खेती

मुनगे की खेती ने बदल दी किस्मत

संवाददाता

मेदिनीनगरः पलामू जिले की महिलाएं स्वालंबी बन रही हैं। वे दूसरों पर निर्भर न रहकर खुद की मेहनत के बदौलत आत्मनिर्भर बन रही हैं। सखी मंडल से जुड़कर महिलाएं अपनी आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ करने में जुटी हैं। जिले के तीन प्रखंड की महिलाएं सखी मंडल से जुड़कर जोहार परियोजना के तहत मुनगा की खेती कर रही हैं। दो तरह से किसान मुनगा की खेती कर रहे हैं। इसमें नर्सरी विधि से तैयार किये गये मुनगा के पौधे को किसानों के बीच वितरण किया गया है। वहीं फॉर्मिंग मॉडल से भी किसान मुनगा की खेती कर रहे हैं। दोनों तरह के पौधों को खेतों में लगाया गया है। पलामू जिले के तीन प्रखंड छतरपुर, पाटन और चैनपुर के 2718 किसान मुनगा की खेती कर रहे हैं। नर्सरी विधि से 60650 मुनगा के पौधे तैयार किये गये और उसे किसानों के बीच वितरित किये गये हैं। वहीं 116 अन्य किसान फार्मिंग मॉडल से मुनगा की खेती करने में जुटे हैं।

प्रखंडवार आंकड़ों को देखें तो छतरपुर प्रखंड के 803 किसानों को 23650 मुनगा के पौधे वितरित किये गये हैं। वहीं 34 किसान फॉर्मिंग मॉडल से खेती कर रहे हैं। पाटन प्रखंड में 901 किसान 21000 पौधे वितरण किये गये हैं। वहीं 42 किसान फॉर्मिंग मॉडल से खेती कर रहे हैं। इसके अलावा चैनपुर प्रखंड के 1014 किसान 16000 किसानों को नर्सरी विधि से तैयार किये गये मुनगा के पौधों का वितरण किया गया है। जबकि 40 किसान फॉर्मिंग मॉडल से मुनगा की खेती करने में जुटे हैं।

●मुनगा की खेती कर स्वालंबी बन रहीं सखी मंडल की महिलाएं
●पलामू जिले के तीन प्रखंडों में की जा रही मुनगा की खेती
●नर्सरी विधि से तैयार किये गये 60,650 पौधे खेती के लिए किसानों के बीच किया गया है वितरण
●मुनगा के जड़ से लेकर फल तक बीमारी और पशु आहार में होता है उपयोगी

पौष्टिकता से भरा है मुनगा का पेड़

मुनगा एक प्रकार का पेड़ होता है, जिसके हर हिस्से का इस्तेमाल किसी न किसी बीमारी के इलाज और पशु आहार में होता है। यूं कहें कि इसके जड़ से लेकर फल तक काफी उपयोगी होता है। मुनगा के पत्तों में बहुत तरह के विटामिन, प्रोटिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, जो न केवल इंसानों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, बल्कि पशुओं के लिए भी आवश्यक है। उसके पत्तों में जख्मों को भरने की भी क्षमता होती है। मुनगा के पत्तों को पशु आहार के तरह इस्तेमाल करने से न केवल बकरियां स्वस्थ रहती हैं, बल्कि उनके वजन में भी बढ़ोतरी होती है। मुनगा की खूबियों की वजह से इसे 'मिरेकल ट्री' यानी जादुई पेड़ भी कहा जाता है।

बकरी पालन करने वालों के बीच दिया जा रहा बढ़ावा

जोहार परियोजना के अंतर्गत मुनगा के खेती को उन किसानों के बीच बढ़ावा दिया जा रहा है, जो बकरी पालन कर रहे हैं। मुनगा की खेती शुरू करने से पहले .. ...शेष पेज 3 पर

कृषि वैज्ञानिकों ने उलिहातु गाँव का भ्रमण किया

संवाददाता

रांची : बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातु गाँव को गोद लेने का निर्णय लिया है। गाँव में कृषि कार्यक्रमों की संभावनाओं के आकलन के लिए बीएयू वैज्ञानिकों के दो दल ने उलिहातु गाँव का भ्रमण किया।दल ने गाँव के पुरूष एवं महिला कृषकों तथा बिरसा मुंडा के पौत्र सुखराम मुंडा से मुलाकात कर स्थिति का आकलन किया।दल ने धान की परती भूमि और धान की खेती उपरांत खाली खेत, सिंचाई के साधन, उद्यान, पशुधन, कृषि वानिकी एवं प्राकृतिक संसाधन की जानकारी से शनिवार को बीएयू कुलपति डॉ आरएस कुरील को अवगत कराया। दल ने गाँव में कृषि क्षेत्र की संभावनाओं पर चर्चा की। कुलपति ने कहा कि उलिहातु गाँव में कृषि कार्यक्रमों को लागु करने में आईसीएआर अटारी निदेशक ने वित्तीय सहायता देने का पत्र मिल चुका है। उन्होंने केवीके, सिमडेगा के वरीय वैज्ञानिक सह प्रधान डॉ शंकर कुमार सिंह को उलिहातु गाँव में पशुधन, जैविक कृषि, मीठी क्रांति, बागवानी, महिला सशक्तिकरण, मूल्यवर्धन, सिचाई साधन का विकास, लाह की खेती आदि से संबंधित कृषि कार्यक्रमों की विस्तृत कार्य योजना अविलंब तैयार कर देने को कहा। इस योजना का आईसीएआर अटारी से स्वीकृति एवं वित्तीय सहयोग से गाँव में जल्द से जल्द सभी कार्यक्रमों को लागु किया जायेगा। कुलपति ने तत्काल उलिहातु गाँव में प्रसार शिक्षा निदेशालय के आईसीएआर क्षमता परियोजना तहत मधुमक्खी पालन से मीठी क्रांति को बढ़ावा देने का निर्देश दिया। गाँव के किसानों को लाभकारी कृषि एवं आय में बढ़ोतरी के लिए तत्काल निदेशालय अनुसंधान तहत संचालित आईसीएआर अखिल भारतीय समन्वित शोध परियोजना के जनजातीय उपपरियोजना के कार्यक्रमों को उलिहातु गाँव में प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। इसके अधीन चालु रबी मौसम में गेहुँ, चना, राई, सरसों एवं तीसी खेती को अग्रिम पंक्ति प्रत्यक्षण, प्रक्षेत्र दिवस और प्रशिक्षण द्वारा तकनीकी प्रसार चलाया जायेगा। गाँव में पशुधन की संभावनाओं को देखते हुए शूकरपालन में झारसुक नस्ल, मुर्गीपालन में झारसिम नस्ल तथा बकरी पालन में ब्लैक बंगाल नस्ल को बढ़ावा तथा पशुधन सुरक्षा हेतु पशु चिकित्सा शिविर व टीकाकरण कार्यक्रम को भी तत्काल चलाया जायेगा।दल में केवीके वैज्ञानिकों में डॉ शंकर कुमार सिंह एवं डॉ हिमांशु सिंह तथा बीएयू महिला वैज्ञानिकों के दल में डॉ निभा बाड़ा, डॉ वलेरिया लकड़ा, डॉ शीला बारला, डॉ शशि किरण तिर्की, डॉ. सुप्रिया सुपल सरीन व टीचिंग एसोसिएट स्नेहा कुमारी शामिल थे।

खाद्यान की गुणवत्ता एवं पोषण सुरक्षा जरूरी: डॉ. कुरील

संवाददाता

16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस पर चर्चा में बीएयू कुलपति डॉ आरएस कुरील पर ने कहा कि स्वास्थ्य भारत में ही देश का भावी विकास टिका है. देश में प्रचुर मात्रा में खाद्यान का उत्पादन हो रहा है. देश के सामने सबसे बड़ी समस्या कुपोषण है. रासायनिक खादों से उत्पादित खाद्यानो में पोषक तत्व कम पाये जाते है. जिसके कारण समाज के बडे तबके में पोषण की कमी से अनेक प्रकार की बिमारिया देखने की जरूरत है. उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों को कृषि उत्पादन में कृषि उत्पादों की गुणवत्ता बनाये रखने पर शोध एवं प्रसार कार्य करने पर बल दिया।

उन्होंने कहा कि संसार में व्याप्त भुखमरी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने एवं इसे खत्म करने के लिए 1980 से 16 अक्टूबर को 'विश्व खाद्य दिवस' का आयोजन शुरू किया गया। इस वर्ष इस दिवस का विषय दुनिया से भुखमरी से हटाना रखा गया है. भारत के मामले में भुखमरी बड़ी समस्या नहीं है। देश में 47% बच्चे कुपोषण की समस्या से जूझ रहे हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार देश में करीब 5 हजार बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं। आज देश के नागरिकों के लिए पोषण युक्त आहार बड़ी समस्या है. उन्होंने कहा कि देश के कृषि वैज्ञानिकों के योगदान से भारत में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान का उत्पादन हो रहा है ऐसा नही है कि पूरे विश्व में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न है। कई देश में इसका संकट है. अफ्रीका जैसे विकासशील देशो में लोग रोज 25 रुपये में अपना गुजारा करते हैं। विश्व के आज अफ्रीका महाद्वीप के रवांडा, नाइजीरिया, इरीट्रिया, कोमोरोस, सूडान, चाड, यमन रिपब्लिक, इथोपिया, मेडागास्कर, जाम्बिया, सोमालिया, सेनेगल, बुरुंडी जैसे देशो में भारी खाद्यान्न संकट है। इसके अलावा इंडोनेशिया, फिलिपीन्स, मोरक्को, हैती, मेक्सिको जैसे देशो की हालत काफी खराब है। वहां पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन नही हो रहा है।

लूटपाट, चोरी की घटनायें बढ़ रही है। इस दिवस पर सभी को शपथ लेनी चाहिये कि कभी भी भोजन को नष्ट नही करेंगे। ये ख्याल रखेंगे की हमारे आस-पड़ोस में कोई भूखा न रहे। शादी, ब्याह जैसे कार्यक्रम में भोजन नष्ट नहीं करेंगे। बचे हुए भोजन को गरीब भूखे बेसहारा लोगो में वितरित करेंगे। जैविक कृषि को बढ़ावा देंगे, जिससे उपज शुद्ध हो, फसल में किसी तरह की अशुद्धि न हो। आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों का इस्तेमाल नही करेंगे। खेतों में जैविक खाद्य का भी इस्तेमाल करेंगे और कृषि प्रदुषण नही फैलायेंगे।

आज पूरे विश्व की आबादी 760 करोड़ है, जो 2050 तक 900 करोड़ होने सी सम्भावना है. बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन की जरूरत है. हमें कभी भी भोजन, अनाज और दूसरी खाद्य सामग्री को नष्ट नही करना चाहिये।

16 अक्टूबर को मना विश्व खाद्य दिवस

मेकॉन ने नई तकनीक अंगारा 7.1 ए स्तर 2 लांच किया

रांची संवाददाता: भारत सरकार के संस्थान मेकॉन लिमिटेड ने नई तकनीक अंगारा 7.1 ए स्तर 2 का लांच किया गया। इस कार्यक्रम में मेकॉन के सीएमडी अतुल भट्ट , निदेशक तकनीकी पी के सारंगी, निदेशक वाणिज्य गौतम चटर्जी, निदेशक पिरयोजना सलिल कुमार, निदेशक आर एच जुनेजा, सीवीओ यू के केडिया, कार्यकारी निदेशक व वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। मेकॉन के सीएमडी अतुल भट्ट ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में मेकॉन ने भारत में लौह और इस्पात उद्योग के विकास आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मेकॉन ने भारतीय उद्योग में नवाचार निरंतरता और प्रौद्योगिकी समाधान के साथ काबिलियत को साबित किया है। आज मेकॉन तकनीक की विरासत को आगे ले जाते हुये मेकॉन ने अंगारा 7.1 ए विकसित किया है। यह स्वचालन के क्षेत्र में अहम भूमिका निभायेगा। अब हमें उम्मीद है कि अंगारा 7.1 ए स्तर 2 स्वचालन के साथ, ऊर्जा दक्षता बढाने के साथ संबंधित उद्योग की उत्पादन में गुणवत्ता व सुधार नजर आयेगा, जो भारतीय स्टील उद्योग में एक नया आयाम साबित करेगा।

क्या असंभव है शुद्ध दुग्ध उत्पाद?

अभी हाल ही में देश भर में कई ब्रांडों के पैकेट बंद दूध की जांच हुयी थी और उनमें से ज्यादतर शुद्धता की कसौटी पर फेल हुये थे। रांची में भी कई ब्रांडों के पैकेट बंद दूध उपलब्ध हैं और यह जांच का विषय है कि ये पैकेट बंद दूध शुद्ध और स्वास्थ्यवर्द्धक हैं? पिछले साल का वाकया है जब फैक्ट्री से चले दूध के कंटेनर को उसके कर्मी ही बीच रास्ते में रोक कर दूध निकाल रहे थे और उसमें प्रदूषित जल मिला रहे थे। जानकारों का कहना है कि देश में दूध की जितनी आवश्यकता है उतना उत्पादन नहीं है, लेकिन पर्याप्त आपूर्ति हो रही है तो अवश्य इसमें कोई घालमेल है। यहां तक कि विदेशी कंपनियों के दुग्ध उत्पाद भी जांच में हानिकारक पाये गये हैं। समाचारों में हम मिलावटी दूध बनाने से लेकर खतरनाक दुग्ध उत्पादों की खबरें देखते हैं। अभी पर्व त्यौहारों का मौसम है और इसमें मिलावटी दूग्ध उत्पादों की बाढ सी आ जाती है।

आप खटालों में भी शुद्ध दूध की उम्मीद नहीं कर सकते। खटाल में पशुओं को अक्सर इंजेक्शन देकर दूध निकाला जाता है जो बच्चों के लिये अत्यंत ही हानिकारक होता है। इसके अलावा मिलावटी चारे की समस्या है जिसके कारण पशु से प्राप्त दूध में गुणवत्ता नहीं होती। पशुपालक ज्यादा लाभ कमाने के चक्कर में पशुओं को खतरनाक दवायें देते हैं ताकि पशु ज्यादा दूध दे।

दुग्ध में कंपनियां खतरनाक रसायनों से लेकर दूग्ध पावडर तक की मिलावट करती हैं जिनको समझना आम लोगों के लिये मुश्किल है। इसके अलावा इनकी पैकेजिंग में लापरवाही यहां तक बरती जाती है कि, आप उसपर छपा हुआ एक्सपायर डेट तक नहीं पढ सकते हैं। पैकिंग में लापरवाही का उदाहरण है कि दुग्ध पैकेट में कॉकरोच तक पाये गये हैं। वास्तव में अब दूध और दुग्ध उत्पादों का शुद्ध मिलना मुश्किल होता जा रहा है।

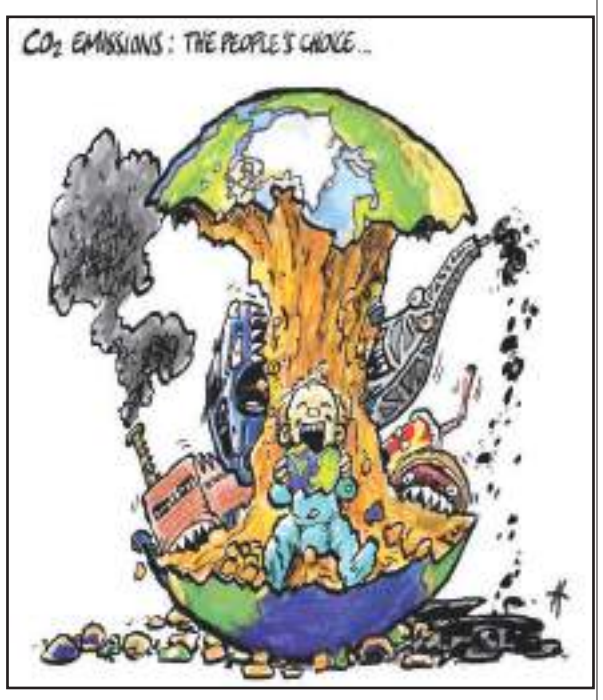

जल संरक्षण एवं शुष्क भूमि तकनीक से राज्य में कृषि का विकास

रांची संवाददाता :बिरसा कृषि विश्वविद्यालय अपने युवा वैज्ञानिकों की टीम को दुनिया के सर्वोत्तम कृषि शोध संस्थानों और प्रयोगशालाओं में भेजेगा ताकि वे वहां की नवीनतम तकनीक और व्यवहार को समझकर उसे झारखण्ड में कार्यान्वित करें और यहाँ के किसानों की तकदीर बदलें। यह घोषण बीएयू के कुलपति डॉ राम शंकर कुरील ने 15 अक्टूबर को रबी अनुसंधान परिषद् की 39वीं बैठक को संबोधित करते हुए की। उन्होंने बीएयू अधिकारियों को नवोन्मेषी विभाग गठित करने सम्बन्धी प्रस्ताव देने का निर्देश दिया।उन्होंने राज्य में कृषि कार्य को गति प्रदान करने के लिए किसानों को प्रशिक्षण देना होगा,उनके लिए प्रमाणपत्र और डिप्लोमा कार्यक्रम चलाना होगा। राज्य में सिंचाई सुविधा में कमी को देखते हुए जल संरक्षण को बढ़ावा एवं सिंचाई जल का समुचित उपयोग सुनिश्चित करना होगा। वर्षपात में असमानता को देखते हुए शुष्क भूमि कृषि तकनीक पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,अयोध्या (उत्तर प्रदेश)के पूर्व कुलपति डॉ बसंत राम ने कहा कि झारखण्ड में खेती बिहार,उत्तर प्रदेश,पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की तरह आसान नहीं है। झारखण्ड में खेती-बारी की ज्वलंत समस्याओं को चिन्हित कर उनका प्रलेखन करने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम गठित करने की आवश्यकता है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान,कानपुर के पूर्व निदेशक डॉ शंकर लाल ने कहा की फसल उत्पादन बढाने के बजाय खेती की लागत घटाकर किसानों की आय दुगुनी करना ज्यादा आसान है .समय पर बोआई,पौधों की पंक्ति के बीच सही दूरी,अंतरवर्ती फसल,जैव उर्वरक तथा जैव कीटनाशी के प्रयोग द्वारा उत्पादन लागत घटाई जा सकती है .उन्होंने कहा कि भारत खाद्यान्न के मामले में जरूर आत्मनिर्भर हो गया है, किन्तु लोगों की, विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में,पोषण आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई हैं .लोगों को आवश्यक मात्र में लौह तत्व, प्रोटीन,खनिज,विटामिन आदि नहीं मिल पा रहे हैं .पोषक तत्वों से भरपूर मडुआ,कोदो,सावां,रामदाना जैसे गौण और कम प्रयुक्त फसलों पर ज्यादा शोध करने की आवश्यकता है। बीएयू के अनुसंधान निदेशक डॉ डी एन सिंह ने कहा की देश में खेती का वर्षाश्रित क्षेत्र 60 प्रतिशत है, जबकि झारखण्ड में लगभग 88 प्रतिशत है .यहाँ औसत वार्षिक वर्षा तो करीब 1400 मिमी होती है, किन्तु उसका 70 प्रतिशा हिस्सा बेकार बहकर नदी,नालों में चला जाता है। इसलिए यहाँ फसल गहनता भी राष्ट्रीय औसत 150 के मुकाबले सिर्फ 125 है। राज्य का कृषि परिदृश्य बदलने के लिए मानसून की बारिश का संरक्षण ही एकमात्र विकल्प है।

बीएयू में शीघ्र ही 40 वर्ष से कम उम्र के वैसे वैज्ञानिकों की एक टीम गठित की जाएगी,जो लीक से हटकर सोचने और करने का माद्दा रखते हैं।

प्रकृति ही देगी प्लास्टिक का हल

डॉ नीलम महेंद्र

इंडिया बनने से पहले जब यह देश भारत था, तो पेड़ के पत्तों के दोने, पत्तल, मिट्टी के कुल्लड़, केले के पत्ते जैसी कटलरी, कागज़ के लिफाफे और कपड़े के थैले, जैसी प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करता था जो स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिहाज से सुरक्षित थीं।

आदमी भी क्या अनोखा जीव है, उलझनें अपनी बनाकर आप ही फंसता है, फिर बेचैन हो जगता है और ना ही सोता है. आज जब पूरे विश्व में प्लास्टिक के प्रबंधन को लेकर मंथन चरम पर है तो रामधारी सिंह दिनकर जी की ये पंक्तियाँ बरबस ही याद आ जाता है । वैसे तो कुछ समय पहले से विश्व के अनेक देश सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग बंद करने की दिशा में ठोस कदम उठा चुके हैं और आने वाले कुछ सालों के अंदर केवल बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का ही उपयोग करने का लक्ष्य बना चुके हैं। भारत इस लिस्ट में सबसे नया सदस्य है. जैसा कि लोगों को अंदेशा था, उसके विपरीत अभी भारत सरकार ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक को कानूनी रूप से बैन नहीं किया है केवल लोगों से स्वेच्छा से इस्का उपयोग बन्द करने की अपील की है. अच्छी बात यह है कि लोग जागरूक हो भी रहे हैं और एक दूसरे को कर भी रहे हैं। अगर दुनिया भर के देशों द्वारा सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन के पैटर्न को देखें तो हमें यह पता चलता है कि हर देश ने विभिन्न चरणों में अपने इस लक्ष्य को हासिल किया है ना कि एक बार में पूरे देश में सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन लगाकर। दरअसल इस के अनेक पक्ष और पहलू हैं। जैसे आज प्लास्टिक एक ऐसी वस्तु बन चुकी है जो हमारी दिनचर्या का ही हिस्सा बन गई है, तो सबसे पहले तो सरकार को लोगों के सामने उसका ऐसा विकल्प प्रस्तुत करना होगा जो उससे बेहतर हो जिसमें थोड़ा वक्त लगेगा। इसके अलावा आज देश की अर्थव्यवस्था भी कुछ कुछ धीमी गति से चल रही है. ऐसे समय में जब सरकार देश की अर्थव्यवस्था को गति पहुँचाने के विभिन्न उपाय आजमा रही हो तो वह सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाकर एक नया आर्थिक संकट नहीं खड़ा करना चाहेगी। लेकिन उसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए कुछ ठोस और बुनियादी कदम तो उठाने ही होंगे क्योंकि आज की स्थिति में भारत में हर साल 1।4 करोड़ टन प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है. इतना बड़ा उद्योग होते हुए भी इस सेक्टर में प्लास्टिक से पैदा होने वाले कूड़े के प्रबंधन की कोई संगठित प्रणाली नहीं है. लेकिन भारत अकेला ऐसा देश नहीं है जो प्लास्टिक के अप्रबंधन के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा हो । विश्व का हर देश इस समस्या से ग्रस्त है. यही कारण है कि विभिन्न देशों की सरकारें इस चुनौती का सामना करने के लिए नए नए रचनात्मक तरीके खोजने में लगी हैं। जैसे इंडोनेशिया की सरकार ने एक पॉलिसी लागू की थी, कि उपयोग की गई प्लास्टिक की बोतलें जमा करने पर मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी जाएगी। जबकि यूनाइटेड किंगडम ने एक पॉलिसी तैयार की है जो 2022 से लागू होगी। इसके अंतर्गत प्लास्टिक का उत्पादन करने वाले उद्योगों में रीसायकल किए पैकेज मटेरियल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्लास्टिक के उत्पादन अथवा आयात पर प्लास्टिक पैकेज टैक्स लगाया जाएगा।

भारत के लिए भी इस विषय पर दुनिया के सामने नए विचार नए इनोवेशन नए आईडिया रखने का यह एक बेहतरीन समय है. सम्पूर्ण विश्व जो आज प्लास्टिक प्रदूषण से जूझ रहा है उसके सामने नए प्राकृतिक विकल्पों से इस समस्या के समाधान का नेतृत्व करने का सुनहरा अवसर भी है और इतिहास भी। क्योंकि इंडिया बनने से पहले जब यह देश भारत था, तो पेड़ के पत्तों के दोने, पत्तल, मिट्टी के कुल्लड़, केले के पत्ते जैसी कटलरी, कागज़ के लिफाफे और कपड़े के थैले, जैसी प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करता था जो स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिहाज से सुरक्षित थीं। और आज के वैज्ञानिक युग में भी प्लास्टिक के सैकड़ों विकल्प हैं। यदि हम निष्पक्ष रूप से देखें तो भारत दूसरे देशों से कच्चे तेल को खरीद कर स्वयं अपने पर्यावरण को प्लास्टिक कचरे में तब्दील कर रहा है लेकिन अब समय आ गया है कि वो नए विकल्पों की खोज का नेतृत्व करके समूचे विश्व को दिशा दिखाए। और अच्छी खबर यह है कि आज अगर प्लास्टिक एक समस्या है तो इस समस्या का समाधान भी है. मशरुम जो खाने में प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत माने जाते हैं वो नवीन खोजों के अनुसार प्लास्टिक का एक बेहतर विकल्प बनने के लिए तैयार हैं। पेड़ों से निकल कर जो फफूंद उगती है वैज्ञानिक उसके रेशों से एक ऐसा मटेरियल बनाने में सफल हो गए हैं जो प्लास्टिक की जगह ले सकता है. सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें किसी भी कृषि उत्पाद के कचरे पर उगाया जा सकता है, ये नेचुरल पॉलीमर होते हैं जो मजबूत से मजबूत गोंद से भी ज्यादा मजबूती से चिपकाने और जोड़ने के काम आते हैं। इसके अलावा जो चट्टानें प्रकृति में बड़ी मात्रा में पाई जाती हैं वैज्ञानिक अब उनसे ऊन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल ज्वालामुखी विस्फोट से लावा निकलकर जब ठंडा हुआ तो यह चट्टानें बनीं। अब इन चट्टानों को स्लैग से मिलाकर स्टोन वूल तैयार किया जा रहा है. इसकी खास बात यह होती है कि इसमें आग नहीं लगती और खराब मौसम में भी यह ऊन खराब नहीं होती। सम्भव है आने वाले समय में यह प्लास्टिक के विकल्प के रूप में उपयोग की जाने लगे।इसी प्रकार दूध की मदद से वैज्ञानिकों ने एक पतली परत वाली प्रोटीन फिल्म तैयार की है जो अधिक तापमान में भी इस्तेमाल की जा सकती है और इसे रीसायकल करना भी आसान है. इसी क्रम में भुट्टे के डंठल, घास,नारियल, सी वीडस आदि पर भी काम करके प्लास्टिक का प्राकृतिक विकल्प खोजने के प्रयास दुनिया भर में किए जा रहे हैं।

लेकिन जब तक हमारे सामने प्लास्टिक का विकल्प नहीं आता, इस पृथ्वी के एक जिम्मेदार वासी के नाते, इस सृष्टि का अंश होने के नाते, सभी जीवों में श्रेष्ठ मनुष्य के रूप में जन्म लेने के कारण अन्य जीवों के प्रति अपने दायित्वों की खातिर कुछ छोटे छोटे कदम हम भी उठा सकते हैं। जब हम बाहर जाते समय अपना मोबाइल लेना नहीं भूलते तो एक कपड़े का थैला ले जाना भी याद रख सकते हैं। ●

घटते वन क्षेत्र की एक वजह ये भी

शंकर अय्यर

जरा कल्पना कीजिए कि गोवा के आकार की तीन गुनी या त्रिपुरा से बड़े वनक्षेत्र की भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया गया है। कल्पना कीजिए कि हजारों करोड़ रुपये की हवाई अड्डे की जमीन अतिक्रमणकारियों के कब्जे में है। कल्पना कीजिए कि बंगलूरू के क्षेत्रफल से भी ज्यादा भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। ये रिप्लेज बिलीव इट ऑर नॉट (एक अमेरिकी फ्रेंचाइजी-अविश्वसनीय जानकारियों का भंडार) की प्रवृष्टियां नहीं हैं ! पिछले महीने सरकार ने सूचना का अधिकार कानून के तहत पूछे गए प्रश्न के जवाब में बताया कि 12,81,397 हेक्टेयर जंगल (12,813 वर्ग किलोमीटर), जो सार्वजनिक संपत्ति है, निजी मुनाफाखोरों के कब्जे में था।

इस कुख्यात सूची में शीर्ष पर मध्य प्रदेश है, जहां 5.34 लाख हेक्टेयर (5,437 वर्ग किलोमीटर) वन भूमि पर, जो जबलपुर से भी बड़ा क्षेत्र है, कब्जा कर लिया गया। उसके बाद स्थान है असम का, जहां 3,712 वर्ग किलोमीटर वन भूमि (तिनसुकिया जिले के बराबर) पर अतिक्रमण है। राजनीतिक मंशा और प्रशासनिक उदासीनता देखने लायक है- प्रधानमंत्री ने अप्रैल, 2016 और जून, 2019 में अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में पेड़ लगाने की बात कही थी, पंद्रहवें वित्त आयोग की तरफ से वन आच्छादन के लिए राज्यों से भूमि के विशेष आवंटन की मांग की गई है और तथ्य यह है कि कतर से भी बड़े भौगोलिक क्षेत्र पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया है। सरकारी संपत्ति का निजी दोहन सिर्फ वन भूमि तक सीमित नहीं है। संसद के मानसून सत्र में 15 जुलाई, 2019 को सरकार ने खुलासा किया कि दिसंबर, 2018 तक 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में

9,622 एकड़ से अधिक रक्षा क्षेत्र की भूमि पर अतिक्रमण था। 2,200 एकड़ से भी अधिक रक्षा भूमि पर अतिक्रमण के साथ उत्तर प्रदेश राज्यों की इस सूची में शीर्ष पर है। सबसे अधिक भूमि के मालिक रेल मंत्रालय ने संसद में खुलासा किया कि 31 मार्च, 2019 तक रेलवे के विस्तार और सुरक्षा के लिए जरूरी 821 हेक्टेयर से ज्यादा यानी करीब 2,000 एकड़ जमीन अतिक्रमण के अधीन थी। एयर इंडिया से लेकर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तक घाटे में चल रहे उद्यमों से जूझते नागरिक उड्डयन मंत्रालय की 979 एकड़ से ज्यादा जमीन अतिक्रमण के अधीन है। इनमें से 308 एकड़ से अधिक जमीन पर अकेले मुंबई में कब्जा है। अतिक्रमित संपत्ति के मूल्य का अंदाजा लगाना हो, तो जरा मुंबई हवाई अड्डे के आसपास की अचल संपत्ति की खरीद-फरोख्त पर गौर कीजिए। इस साल की शुरुआत में एक जापानी कंपनी ने हवाई अड्डे से सटे बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एक एकड़ जमीन के लिए 2,400 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी। बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स सौदे के दसवें हिस्से को ही हवाई अड्डे की जमीन का मूल्य मान लें, और अतिक्रमित 308 एकड़ भूमि का मूल्य निकालें, तो जमीन की कीमत पांच अंकों में पहुंच सकती है। अतिक्रमण की इस भयावह कहानी के कई पहलू हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में भारत सरकार ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्मारकों की देखभाल करती है। इस ग्रीष्म ऋतु में सरकार ने खुलासा किया कि 321 स्मारकों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। सर्वाधिक अतिक्रमण वाले राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है, जहां 75 स्मारक अतिक्रमण के अधीन हैं, जिनमें से 25 यानी एक तिहाई राज्य की राजधानी लखनऊ में हैं।

व्यवस्थागत निष्क्रियता से अतिक्रमण को बढ़ावा मिलता है। केंद्र सरकार के हर विभाग के पास एक सुविधाजनक विकल्प है कि वह सरकारी संपत्ति /भूमि / वनों के अवैध कब्जे का दोष राज्य सरकारों पर डाल देता है और हर शिकायत या प्रश्न के जवाब में कहता है कि 'अतिक्रमण राज्य का विषय है।' ऐसा नहीं है कि राज्य सरकारें अपनी देखरेख वाली भूमि की रक्षा के लिए कोई बेहतर काम कर रही हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट के तथ्य दिमाग को सुन्न करने वाले हैं। राजस्थान पर जारी 2019 की कैग की रिपोर्ट कहती है, दस तहसीलों में 3,101 उपद्रवियों ने घर, व्यावसायिक, औद्योगिक एवं ईंट भट्ठे के निर्माण के लिए 30.77 लाख वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। सबसे बुरी बात थी कि सरकारी भूमि के डेटाबेस को बनाए रखने के लिए कोई केंद्रीकृत प्रणाली नहीं थी।

सिर्फ राजस्थान ही व्यवस्थागत सुस्ती का शिकार नहीं है। 2018 में कैग की रिपोर्ट थी कि कर्नाटक में 1.92 लाख एकड़ सरकारी जमीन (बंगलूरू से बड़ा क्षेत्र) अतिक्रमण के अधीन थी और 2,608 प्राप्त शिकायतों में से 1,856 शिकायतें सत्यापन और बेदखली के लिए लंबित थीं। 2018 की ही महाराष्ट्र की कैग रिपोर्ट में बताया गया कि ठाणे में 30-35 वर्ष पहले एक झील थी, जहां अब झुग्गी बस्ती है, जिनमें 300 से 350 घर हैं और शेष खाली जमीन का इस्तेमाल गाड़ियां खड़ी करने के लिए होता है। ईंट भट्ठों के लिए 1.74 लाख वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है।

ये उदाहरण समस्या की गंभीरता के प्रतीक हैं। बड़े पैमाने पर अतिक्रमण और दशकों से उसकी मौजूदगी स्पष्ट रूप से राजनीतिक संरक्षण और मंजूरी की पुष्टि करते हैं-चाहे वन भूमि का अतिक्रमण हो या व्यावसायिक दोहन के लिए सरकारी जमीन का। राज्य दर राज्य ईंट भट्ठों के लिए जमीनें हड़पी जा रही हैं, जो जाहिर है, राज्य सरकार के विभागों की सहभागिता के बिना संभव नहीं है। कानून या कानूनी प्रावधान की कोई कमी नहीं है। कमी है, तो जवाबदेही की। हरेक सरकारी विभाग में कहीं न कहीं कोई व्यक्ति सरकारी कब्जा और इस तरह सरकारी संपत्ति का स्वामित्व बरकरार रखने के लिए जिम्मेदार होता है।

दुख की बात है कि कानून के राज का पालन इस बात पर निर्भर करता है कि शासन कौन कर रहा है। निजी मुनाफाखोरी के लिए सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जे का अपराध उस सहज व्यवस्थागत गठजोड़ का प्रतिनिधित्व करता है, जो राजनीतिक भ्रष्टाचार को जन्म देता है। सवाल यह है कि राजनीतिक वर्ग इसके जरिये करदाता नागरिकों को क्या संदेश दे रहा है?

थर्मोइलेक्ट्रिक जेनरेटर दूर कर सकते हैं ऊर्जा का गतिरोध

देवांशु दत्ता

सौर ऊर्जा हरित आंदोलन के आधारस्तंभों में से एक है। जहां सौर उपकरण विनिर्माता पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, वहीं इसने जीवाश्म ईंधनों की जरूरत कम कर दी है। लेकिन सौर ऊर्जा की एक बड़ी खामी भी है। उसमें निरंतरता की कमी है। रात के समय पडने वाले गतिरोध के अलावा ध्रुवों के नजदीक ऐसे इलाके भी हैं जहां कई महीनों तक सूर्य दिखता ही नहीं है। इसका मतलब है कि वहां अन्य ऊर्जा स्रोतों की भी जरूरत है। ऐसा ही एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत 200 वर्षों से प्रचलित परिघटना का दोहन कर सकती है। यह स्रोत थर्मोइलेक्ट्रिसिटी है यानी तापमान भिन्नता से पैदा होने वाली बिजली। कई तरह के प्रायोगिक थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटरों का प्रयोगशाला एवं वास्तविक हालात में परीक्षण किया जा रहा है। इटली के वैज्ञानिक अलेसांद्रो वोल्टा ने 1790 में पाया था कि ताप भिन्नता होने पर विद्युत-धारा एक सर्किट के जरिये प्रवाहित होती है। इसके उलट अगर कोई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो ताप भिन्नता की स्थिति पैदा होती है। थॉमस सीबेक और ज्यां-चार्ल्स पेटियर ने 1820 के दशक में इस धारणा को और परिष्कृत किया।

लॉर्ड केल्विन ने भी 1850 के दशक में इस पर शोध कर प्रभावों को परिभाषित करने वाले अहम समीकरणों के बारे में बताया। किसी घर की भीतरी एवं बाहरी दीवारों के बीच भी प्राकृतिक रूप से ताप विभेद हो सकती है। इन प्राकृतिक ताप भिन्नताओं का चतुराई से प्रयोग कर थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटरों का निर्माण किया जा सकता है।

बचाना होगा हिमखंडों को

गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के वनाधिकारी ने इस हिमखंड के टुकड़ों के चित्रों से इसके टूटने की पुष्टि की थी। ग्लेशियर वैज्ञानिक इन घटना की पृष्ठभूमि में कम बर्फबारी होना बता रहे हैं। इस कम बर्फबारी की वजह धरती का बढ़ता तापमान बताया जा रहा है। इससे हिमखंडों में दरारें पड़ गई थीं और इनमें बरसाती पानी भर जाने से हिमखंड टूटने लग गए।दक्षिणी ध्रुव के बर्फीले अंटार्कटिका में हजारों साल से बर्फ के विशाल हिमखंड के रूप में मौजूद हिमखंड का एक भाग पिछले दिनों टूट गया। हिमखंड का टूटा हिस्सा इतना विशालकाय था कि इस पर दिल्ली, मेरठ और गाजियाबाद को बसाया जा सकता है। वैज्ञानिक इसके टूटने की भविष्यवाणी पहले ही कर चुके थे। हालांकि हिमखंडों का टूटना कोई नई बात नहीं है।

मिट्टी की सेहतः आधुनिक खेती के तरीकों से जुड़े ज्ञान की कमी

रमेश ठाकुर

कृषि आमदनी में घाटे का प्रमुख कारण कृषकों में आधुनिक खेती-किसानी के तरीकों से संबंधित ज्ञान की कमी है। कृषि में मृदा तकनीक कितनी उपयोगी साबित हो सकती है, इस सच्चाई से अन्नदाता फिलहाल वाकिफ होने लगे हैं। ग्लोबल वार्मिंग का असर कहें या नित बदलते मौसम की विषमताएं, इससे कृषि पद्धतिसंकट में पड़ गई है। कृषि और किसानों की इस पीड़ादायक समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने पूरे देश में किसानों की सुविधाओं के लिए मृदा विज्ञान का प्रचार-प्रसार तेजी से शुरू किया है।

इसके तहत किसानों को कौन-सी फसल कब और किस तरह की मिट्टी में बोनी है, इसकी उपयुक्त जानकारी सुलभ कराई जा रही है। मृदा जांच तकनीक से खेत की मिट्टी को कैसे उपजाऊ बनाया जाए, फसलों को कीटनाशकों से किस तरह से बचाया जाए और कौन-सी खाद कब देनी है, इसकी जानकारियां मुहैया कराई जा रही हैं।

खेती-किसानी का स्वरूप बदल चुका है। ऐसे में, किसानों को बदलते समय के साथ ही चलना होगा। कायदा तो यही बनता है कि फसल लगाने से पहले किसान खेत की मिट्टी की स्थानीय कृषि प्रयोगशाला में जांच कराए। उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही उचित फसल की बुआई की जानी चाहिए। बिना जांच के खेतों में अत्यधिक रासायनिक प्रदार्थों के प्रयोग से हवा, पानी, व मृदा प्रदूषण में लगातार वृद्धि हो रही है। मानव स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है।

देश के दर्जनों राज्य ऐसे हैं, जहां के किसान पूर्णतः विज्ञान आधारित कृषि पर निर्भर हो गए हैं। वैज्ञानिक तकनीक अपनाने के बाद उनकी फसलों की उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही, उनको फसलों से रोगरोधी,

कीटाणुरोधी, अनुवांशिक रोगों से मुक्ति का रास्ता भी मिला है। दरअसल जब फसल पककर तैयार होती है, तब आनुवांशिक कीट लग जाते हैं, जिससे खड़ी फसल चौपट हो जाती है। सरकार ने पूरे देश में 'किसान मेले' का आयोजन शुरू किया है, जिसमें किसानों को कृषि से संबंधित तमाम नवीनतम दवाओं की जानकारी दी जाती है। मेले के जरिये किसानों को उन्नत खेती के तरीके भी सिखाए जाते हैं।

मृदा परीक्षण के बाद किसानों को फसलों की बुआई से दवा छिड़कने तक आसानी हो जाती है, और उत्पादन बढ़ने की भी गारंटी रहती है। दरअसल मौजूदा जमीनें पहले जैसी उपजाऊ नहीं रहीं। रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित प्रयोग का मृदा उर्वरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और फसलों की गुणवत्ता और पैदावार में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है।अन्नदाताओं को मृदा जांच कराने के बाद विशेषज्ञों द्वारा दी जाने वाली सलाह के उपरांत ही खाद और अन्य रसायनों-कीटनाशकों का इस्तेमाल अपने खेतों में करना चाहिए। फसल लगाने से पहले मिट्टी की जांच से खेत में उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा, अम्लीयता, क्षारीयता, कार्बनिक पदार्थ मृदा की भौतिक संरचना और किसी फसल विशेष के लिए भूमि की उपयुक्त जानकारी मिल जाती है।

मृदा जांच से अधिकांश मिट्टी में कैल्शियम, मैग्नेशियम, लोहा, जस्ता, मैग्नीज, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, गंधक, बोरोन, मोलीब्डेन, तांबा, क्लोरीन आदि पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों की मानें, तो हर किसान को अपनी सघन खेती वाले क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष और एकल फसल वाले क्षेत्र में तीन साल के अंतराल पर मिट्टी की जांच करवानी चाहिए।

सीसीएल एसओपी के माध्यम से कर्मियों को जागरूक कर रहा है

''सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2019'' के अंतर्गत सीसीएल मुख्यालय के एचआरडी विभाग में सीसीएल के सीवीओ ए.के. श्रीवास्तव, निदेशक (कार्मिक) आर.एस. महापात्र, निदेशक तकनीकी (संचालन) वी.के. श्रीवास्तव एवं निदेशक तकनीकी (योजना/परियोजना) भोला सिंह की उपस्थिति में मुख्यालय सहित सभी क्षेत्र से आये अधिकारीगण के समक्ष विद्युत व यांत्रिकी तथा सीएमसी से संबंधित ''स्टैन्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर'' (एसओपी) पर विस्तार से चर्चा किया गया। सीवीओ ए.के. श्रीवास्तव ने अपने संबोधन में कहा कि सीसीएल अपने संगठन के भीतर एसओपी के माध्यम से पारदर्शिता तथा एकरूपता लाकर अपने कर्मियों को जागरूक कर रहा है। उन्होंने कहा कि सीसीएल के विभिन्न विभागों ने एसओपी बनाया है जिससे कंपनी में उत्तरदायित्व (Accountability) की नयी संस्कृति का निर्माण हो रहा है और कंपनी की कार्यशैली में सकारात्मक बदलाव आया है। उन्होंने अपने संबोधन में एसओपी गठन करने की महत्ता पर बल देते हुए कहा कि इससे कर्मियों को अपने-अपने क्षेत्र में कार्य करना सुगम होगा और अपने से संबंधित कार्य के प्रति ही संबंधित अधिकारी जिम्मेवार होंगे।

बीएयू में रबी प्रसार शिक्षा परिषद् के आयोजन में बोले वीसी डॉ. आर. एस. कुरील

किसानों की आय दुगुनी करने की तकनीक पर काम करें वैज्ञानिक

संवाददाता

राज्य में कृषि तकनीकी प्रसार को प्रभावी ढंग से सभी जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) के माध्यम से कार्यान्वित करने हेतु बीएयू ने पहली बार रबी प्रसार शिक्षा परिषद् का आयोजन 16 अक्टूबर को किया गया.बैठक की अध्यक्षता करते हुए बीएयू कुलपति डॉ आरएस कुरील ने विश्वविद्यालय वैज्ञानिकों को गाँव के ग्रास रूट स्तर तक किसानों की आय दुगुनी में प्रभावी चिन्हित तकनीकों के प्रचार झ प्रसार पर बल दिया. उन्होंने कहा कि बेहतर कृषि तकनीकों से किसानों की आय दुगुनी से चार गुनी तक किया जाना संभव है. केवीके संस्थानों के कार्यक्रम पर पूरे देश की नजर है. केंद्र सरकार द्वारा केवीके के माध्यम से विभिन्न नये - नये कार्यक्रमों से जोड़ा जा रहा है. जिला स्तर के केवीके कार्यक्रमों को लागु करने में किसानों की पूर्ण भागीदारी तथा वैज्ञानिकों द्वारा कार्यक्रमों के प्रभाव का अध्ययन, आकलन एवं समीक्षा को प्राथमिकता देनी होगी.

कुलपति ने कहा कि सभी केवीके में पशु शैक्षणिक प्रक्षेत्र की स्थापना, प्रत्येक जिले के एक गाँव में पशु क्षेत्र मॉडल स्थापित करने, लाइन एवं सरकारी विभागों से नजदीकी एवं बेहतर समन्वय पर जोर दिया. मौके पर

उन्होंने राज्य में केवीके कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए कुलपति ने डॉ सुशील प्रसाद, प्रो डीके रुसिया एवं डॉ केके झा की तीन सदस्यीय समिति गठित की घोषणा की. यह समिति प्रत्येक माह सभी केवीके का भ्रमण कर उनकी गतिविधियों एवं कार्यक्रमों की समीक्षा एवं सामाजिक अंकेक्षण करेगी. कुलपति ने आय दुगुनी करने के तकनीकों से सबंधित वैज्ञानिकों में डॉ नरेंद्र कुदादा, डॉ एके सिंह, डॉ एमके चक्रवर्ती एवं डॉ एमएस मल्लिक को केवीके का भ्रमण एवं प्रसार की जिम्मेदारी दी.

एक्सपर्ट पूर्व कुलपति नरेंद्र देव कृषि एवं प्रोद्यागिकी विवि, अयोध्या डॉ बसंत राम ने केवीके की बढती भुमिका को देखते हुए मशिनरी मोड में संचालन तथा कार्यक्रमों पर किसानों की नियमित राय लेने की बात कही. एक्सपर्ट पूर्व निदेशक, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर डॉ शंकर लाल ने किसानों की मांग एवं आसानी से अपनाये जाने वाले तकनीकों के व्यापक प्रसार पर बल दिया.

एक्सपर्ट आईएआरआई, नई दिल्ली के प्रधान वैज्ञानिक डॉ सत्यप्रिय ने किसान हित में सभी केवीके में टेक्नोलॉजी कैफेटेरिया को स्थापित करने तथा अधिक उत्पादन की जगह गुणवत्ता युक्त एवं मूल्य वाली उत्पादों को प्राथमिकता देने की सलाह दी.

एक्सपर्ट डॉ आरके दोहरे, प्राध्यापक प्रसार,नरेंद्र देव कृषि एवं प्रोद्यागिकी विवि, अयोध्या ने किसानों को कम रासायनिक उ-र्वरको के प्रयोग से स्वास्थ्यवर्धक खाद्यान उत्पादन को बढ़ावा एवं नवीनतम तकनीकों से अद्यतन जानकारी देने की बात कही.

मौके पर डीन एग्रीकल्चर डॉ एमएस यादव, डीन वेटनरी डॉ एमपी सिन्हा, डॉ सुशील प्रसाद, प्रो डीके रुसिया, डॉ नरेंद्र कुदादा, डॉ एके सिंह, डॉ एमके चक्रवर्ती, डॉ एमएस मल्लिक एवं डॉ केके झा ने किसानों की आय दुगुनी करने के चिन्हित तकनीकों पर प्रकाश डाला. बैठक में सभी 24 केवीके प्रधान, 3 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र के सह निदेशक सहित विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों एवं किसान प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

मुनगे की खेती ने बदल दी किस्मत .....पेज 1 का शेष

सखी मंडल की सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में उन्हें मुनगा की खेती से संबंधित जानकारी दी गयी। पलामू जिले के तीनों प्रखंडों में नर्सरी विधि से मुनगा का पौधा तैयार कर खेतों में लगाया जा रहा है।

सिंचाई के लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं

मुनगा की खेती दो तरह से की जा सकती है। एक नर्सरी के माध्यम से पौधा तैयार कर और दूसरा सीधा खेत में। मेढ़ बनाकर इसके पौधे लगाये जाते हैं। पौधा से पौधा की दूरी करीब एक फीट और दो मेढ़ों के बीच की दूरी करीब ढाई फीट का होता है। इसमें जैविक खाद और कीटनाशक दिया जाता है, ताकि कीटनाशक से पौधे का नुकसान नहीं हो। इसके पौधे में सिंचाई के लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी खेती किसी भी प्रकार के मिट्टी में आसानी से की जा सकती है।

प्रशिक्षण से जाना मुनगा का गुण

पाटन प्रखंड के कोल्हुआ गांव निवासी लक्ष्मी बाला देवी और चैनपुर प्रखंड के चांदो गांव निवासी सरिता देवी भी मुनगा की खेती कर रही हैं। लक्ष्मी बाला देवी और सरिता देवी ने बताया कि वे लोग क्रमशः 4 डिसमिल और 6 डिसमिल जमीन पर मुनगा की खेती कर रही हैं। वे झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाईटी (जेएसएलपीएस) के जोहार परियोजना द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर खेती प्रारंभ की हैं। प्रशिक्षण में मुनगा की खेती करने से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गयी। मुनगा का पेड़ आसपास भी होता था, लेकिन प्रशिक्षण के पूर्व उसके महत्व का नहीं जानते थे। साथ ही मुनगा के पत्ता और फल बीमारियों में भी फायदेमंद होता है, इसकी भी जानकारी नहीं थी। प्रशिक्षण के बाद उसके गुणों के बारे में जाना। मुनगा पशु आहार में भी उपयोगी और फायदेमंद है, इसके संबंध में भी जानकारी प्राप्त हुई। इसकी खेती करने से बीमारियों का इलाज भी हो सकेगा। साथ ही बकरियों को बिना पैसा खर्च किये पौष्टिक आहार देने में सक्षम हो पाएंगे।

मुनगा की खेती को दिया जा रहा बढ़ावा : उपायुक्त

उपायुक्त डॉ0 शांतनु कुमार अग्रहरि ने बताया कि पलामू जिले में भी सखी मंडल की महिलाएं मुनगा की खेती कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। मुनगा का पेड़ कई गुणों से भरपूर होता है। झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के जेएसएलपीएस द्वारा ग्रामीणों को जोहार परियोजना के अंतर्गत इसकी खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। विशेषकर बकरी पालन करने वाले किसानों को मुनगा की खेती में आगे लाया जा रहा है, ताकि वे पशुपालन की ओर प्रेरित होंगे। मुनगा की खेती से वे पशुओं को पौष्टिक आहार दे पाएंगे, इससे उन्हें बाहर से आहार लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे पैसे का भी बचाव कर सकेंगे।

खेल प्रतिभा तराशना, हम सबकी जिम्मेदारी : सीएमडी सीसीएल

सीसीएल अंतर ग्रामीण फुटबॉल टूर्नामेंट

संवाददाता

रांची :सीसीएल द्वारा 13 अक्टूबर को सीसीएल के ढोरी क्षेत्र स्थित 'शारदा कॉलोनी फुटबॉल ग्राउंड'' में ''अंतर ग्रामीण फुटबॉल टूर्नामेंट'' का शुभारंभ मुख्य अतिथि माननीय सांसद (गिरिड-ीह) चंद्र प्रकाश चौधरी, वि-शिष्ट अतिथि सीसीएल के सीएमडी गोपाल सिंह, पूर्व सांसद रविंद्र पांडेय ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। बॉल किक कर अतिथिगणों ने उदघाटन मैच का प्रारंभ किया।

टूर्नामेंट में 32 टीमें भाग ले रही है जिसमें ढोरी सीएसआर कमांड क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न गांवों की टीम है । उदघाटन मैच सीसीएल ढोरी एवं दादा स्पोर्टिंग बीच खेला गया जो प्रतिस्पर्द्धात्-मक था। यह मैच ड्रा रहा दोनों मैच की प्रत्येक टीम के पांच सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया।

मुख्य अतिथि माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने सीसीएल का धन्यवाद देते हुए कहा की सीएमडी गोपाल सिंह के कुशल नेतृत्व में सीसीएल कोयला उत्पादन के साथ-साथ विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत खेल पर भी ध्यान दे रहा है जो सराहनीय है` उन्होंने कहा कि इन योजनाओ का और विस्तार किया जाना चाहिए जिससे क्षेत्र के सभी जन तक इसका लाभ पहुंचे। सीएमडी गोपाल सिंह ने अपने संबोधन सभी प्रतिभागी टीमों के बच्चों का शुभकामानएं देते हुए कहा कि सीसीएल की प्राथमिकता 'गरीब, ग्रामीणों एवं

श्रमिकों की सर्वांगीण है' और इसी के अंतर्गत आज ग्रामीण फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खेलने से टीम भावना, एकजुटता के साथ साथ खिलाड़ी ऊर्जावान होते हैं, जिससे समाज का समावेशी विकास होता है । गोपाल सिंह ने कहा कि झारखण्ड की खेल प्रतिभा को तराशने की जिम्मेदारी हम सबकी है। उन्होंने सभी युवा प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि आप सभी पूरी लगन, मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। यह हम सबकी नैतिक दायित्व है कि हम यह सुनिश्चित करें कि झारखंड के प्रतिभावान खिलाड़ियों को सारे संसाधन उपलब्ध कराएं और इसके लिए सभी की सहभागिता आवश्यक है, ।सीसीएल सीएमडी गोपाल सिंह के मार्गनिर्देशन में सीसीएल के कमांड क्षेत्रों में ''ग्रामीण फुटबॉल टूर्नामेंट'' के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान खिलाड़ियों को खोजने एवं उन्हें तराशने के लिए सीसीएल के सभी क्षेत्रों में इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। सीसीएल कोयला उत्पादन के साथ-साथ समाज एवं राष्ट्र के समावेशी विकास के लिए सदैव तत्पर है। इस दिशा में खेल विकास एक महत्वपूर्ण एवं सशक्त कड़ी है।

सीसीएल विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जैसे कि जेएसएसपीएस (सीसीएल एवंझारखंड सरकार की एक संयुक्त पहल), ग्रामीण फुटबॉल टूर्नामेंट, समर कैम्प आदि के माध्यम इस दिशा में कार्य कर रहा है। इस अवसर पर महाप्रबंधक (बी.एण्ड के.) एम.के. पंजाबी, महाप्रबंधक (कथारा) पी. चन्दा, महाप्रबंधक (ढोरी) श्री पी. वाजपेयी तथा क्षेत्रिय सीसीएल कर्मी, श्रमिक प्रतिनिधिगण सहित बड़ी संख्-या में दर्शको ने फुटबॉल मैच का आनंद उठाया। स्वागत भाषण महाप्रबंधक ((ढोरी) पी. वाजपेयी ने किया टूर्नामेंट को सफल बनाने में प्रबंधक (खेल) आदिल हुसैन एवं स्थानीय प्रबंधन सहित ग्रामीण भाईयों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा।

पर्यावरण संरक्षण और आय का जरिया बन रहा आम

- मनरेगा के तहत हुटूकदाग के 14 एकड़ भूमि पर लगा आम का पौधा, 2020 में निकलेगा फल
- एक पौधे से 2 से 3 हजार रूपये की होगी आमदनी

संवाददाता

पलामू: जिले के छतरपुर प्रखंड क्षेत्र स्थित हुटूकदाग गांव जिले के लिए अनोखा उ-दाहरण पेश कर रहा है। यहां के 9 किसानों ने सामूहिक रूप से 14 एकड़ भूमि पर आम की बागवानी कर मिशाल कायम की है। 14 एकड़ की भूमि पर लगे हजारों पौधे तैयार हो चुके हैं। आम्रपाली और मल्लिका किस्म के पौधे पलामू जिला प्रशासन के प्रयास से मनरेगा के तहत जुलाई 2017 में लगवाया गया था। बौनी किस्म के इस पौधे में 2019 में मंजर आना प्रारंभ हो गया था, लेकिन छोटे और मजबूत पौधे नहीं होने के कारण इसके मंजर को झाड़ दिया गया। बागवानी किये किसानों ने बताया कि वर्ष 2020 में लगने वाला फल को तैयार होने के लिए छोड़ दिया जायेगा। किसानों ने बताया कि पौधे की हरियाली से उनका मन प्रफुल्लित होता है। बागवानी में घास, कीट, पतंगों की सफाई में लगे रहते हैं। आम के पौधे से आमदनी की उम्मीद पाल रखे किसानों ने जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया है, जिसके प्रयास से आम का पौधा लगवाया गया है। आम की बागवानी करने वाले किसानों में जवाहर मेहता, अमरदेव सिंह, यदु सिंह, विजय सिंह, बिगती कुंवर आदि शामिल हैं। किसानों ने बताया कि एक पौधे से उन्हें 2 से 3 हजार रूपये की आमदनी होगी। वहीं हजारों पौधों की फल से वे मालामाल होंगे।

जल संचयन और पटवन का अनोखा प्रयोग

हुटूकदाग में आम के पौधों की हरियाली आमजनों का ध्यान आकर्षित करता है। वहीं बागवानी परिसर में जल संचयन का

प्रयोगात्मक विधि भी नजर आता है। जल संचयन के लिए बागवानी परिसर में ही जगह-जगह 60/40 का गड्ढा खोदा गया है। इसमें बारिश का पानी संचय होता है, जो बागवानी के सिंचाई में सहायक होती है। मनरेगा योजना के तहत किसान अमरदेव सिंह के खेत में कूप का भी निर्माण कराया गया है। वहीं बागवानी की पटवन के लिए पंपसेट भी लगाया गया है। 200 फीट फा-इवर पाइप भी भूमि संरक्षण विभाग की ओर से प्रदान किया गया है। 14 वें वित की राशि से बड़ा हॉज भी बनवाया गया है, जिसमें पानी स्टोर रखा जा सके। गड्ढे का पानी भूमि जल स्तर को भी बढ़ा रहा है, वहीं संचित पानी पटवन के काम में लाया जा रहा है। स्वयंसहायता समूह की ओर से घास कटिंग करने वाला एक रोलर मशीन भी मिला है।

बागवानी में इस्तेमाल हो रहा है जीवामृत

कृषि विभाग की ओर से उन्हें स्प्रे मशीन तथा जीवामृत (जीव अमृत) बनाने के उपकरण व संसाधन उपलब्ध कराये गये हैं। साथ ही इसके लिए उन्हें प्रशिक्षित भी किया गया है। आम की इस बागवानी में किसान जीवामृत का प्रयोग करते हैं। रसायनिक उ-र्वरकों में किसान अपनी गाढ़ी कमाई को खर्च नहीं करना चाहते। इसके जगह वैकल्पिक तौर पर बागवानी परिसर में ही जीवामृत तैयार कर पौधों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। किसानों ने बताया कि जीवामृत को गौ-मूत्र, गोबर, गुड़, दीमक की मिट्टी, बेसन, आंटा और पानी मिलाकर बनाया जाता है। सभी के मिश्रण को सप्ताह तक सड़ाया जाता है, उसके बाद वह जैवीक खाद के रूप में जीवामृत तैयार होता है। वे इसका प्रयोग आम के बागवानी में करते हैं, जो पौधे की वृद्धि और विकास में सहायक होता है। यह जीवामृत पौधों को रोगाणुओं से बचाता है तथा पौधे को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। रासायनिक उर्वरक के प्रयोग से जमीन की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। इससे पौधों का विकास संभव नहीं होता, इसलिए खुद से वे लोग जीवामृत बनाकर पौधों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं।

किसानों की आमदनी बढ़ेगी

उपायुक्त डॉ0 शांतनु कुमार अग्रहरि ने कहा कि किसान आम का पौधा लगाकर मालामाल हो सकते हैं। बागवानी किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने का जरिया रहा है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण में भी यह महत्वपूर्ण भमिका निभाता आ रहा है। प्डपायुक्त ने बताया कि आम की खेती के माध्यम से किसानों के आर्थिक संवर्द्धन के लिए ग्रामीण विकास, कृषि, भूमि संरक्षण विभाग को समेकित रूप से किसानों को संसाधान मुहैया कराने का निर्देश भी दिया है, जिससे किसान और अधिक उत्साह के साथ बागवानी करने के लिए प्रेरित हो सकें। उन्होंने यह भी कहा कि चौथे वर्ष से आम के एक पौधेसे 2 से 3 हजार रूपये की आमदनी होगी।

नदियों को बचाकर ही बचेंगे हम वरना भुगतने होंगे दुष्परिणाम

सुभाष चंद्र कुशवाहा

हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने देश की 351 नदियों में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की है और नदियों में बढ़ते प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए उसने निगरानी के लिए सेंट्रल मानिटरिंग कमेटी का गठन किया है। हम जानते हैं कि मानव सभ्यता का विकास नदियों के किनारे हुआ है, फिर भी हम नदियों को तबाह करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। नदियां हमारी संपदा हैं। उन्हें साफ और सुरक्षित रखा जाना चाहिए। अगर हम उसे प्रदूषित करते रहेंगे, तो वह दिन दूर नहीं, जब नदियां सदा-सदा के लिए समाप्त हो जाएंगी। यह आशंका निर्मूल नहीं है। नदियों में गिर रहे सीवर, गंदे नाले और उनमें घुले रसायन, उनके प्रवाह और जल संरक्षिता को लगातार समेट रहे हैं। मुनाफा कमाने वाली कंपनियों के अवशिष्ट बिना शोधन के नदियों के बहा दिए जाते हैं। यहां तक कि सल्फ्यूरिक एसिड जैसे खतरनाक रसायन भी बहाए जाते हैं। प्रदूषण नियंत्रणकारी संस्थाएं निष्प्रभावी रही हैं। दुनिया भर के देश अपनी नदियों और उनके तटों को साफ-सुथरा रखने, उनके उद्गम को सदानीरा बनाए रखने में जी-जान से लगे हुए हैं। उनमें सीवर या नालों का कचरा नहीं गिराया जाता। वहां नदियों में धार्मिक अनुष्ठानों के नाम पर फूल-माला, राख, लाश, लकड़ी बहाने की संस्कृति नहीं है। एक स्वस्थ नदी का पानी, न केवल जलीय जीवों को स्वस्थ रखता है, अपितु उससे सिंचित फल और सब्जियां विषाक्त नहीं होतीं। उन नदियों से प्राप्त होने वाली मछलियों में हानिकारक तत्व नहीं पाए जाते, जबकि हमारी नदियों की मछलियों में शीशे की मात्रा खतरनाक स्तर तक पाई जा रही है। गर्मी के मौसम में कई नदियों में डाले जा रहे कचरे की वजह से ऑक्सीजन की इतनी कमी हो जाती है कि मछलियों का दम घुटने लगता है। गोमती, यमुना और घाघरा जैसी नदियों में मछलियों को दम तोड़ते देखा गया है। नदियों को कचरा निस्तारण का जरिया समझने का दुष्परिणाम यह हुआ है कि आज हमारी तमाम नदियां गर्मी के मौसम में सूखने लगी हैं। कई नदियों का अस्तित्व तो अब कागजों में सिमटकर रह गया है।

कई सहायक नदियां सदा-सदा के लिए सूख चुकी हैं। गुजरात तथा राजस्थान की लगभग अधिकांश

नदियां नाम मात्र को बहती हैं। उत्तर-खंड और हिमाचल की तमाम नदियों के उद्गम सिमट गए हैं। इसका प्रभाव गंगा और यमुना जैसी महत्वपूर्ण नदियों पर भी पड़ा है। ऐसा क्यों है कि जिन नदियों को हम मां मानते हैं, उन्हीं का गला घोंट रहे हैं?सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार नदियों में मूर्ति विसर्जन को रोका है। प्रशासन को मूर्ति विसर्जन की वैकल्पिक व्यवस्था करने का निर्देश दिया है, मगर हुआ क्या? इस बार भी दुर्गा पूजा के बाद नदियों में मूर्तियां विसर्जित की गईं। हमारे तमाम मेलों और धार्मिक स्नान के समय अशिक्षित जनता द्वारा नदियों में कचरा डाला जाता है। नदियों को संवारने के बजाय उन्हें कूड़ा फेंकने की जगह समझा जाता है। नदियों की साफ-सफाई की चिंता करते दशकों बीत गए। गंगा को साफ करने के नाम पर अरबों फूंक दिए गए, मगर गंगा आचमन योग्य न रही। दूसरी नदियों का तो कोई पुरसाहाल नहीं है। मेरठ जिले में एक नदी है हिंडन। विकास का अभिशाप झेलती इस नदी को गंदे नाले में तब्दील कर दिया गया है। आज यह नदी कैंसर, बुखार, खुजली, और मच्छरों से होने वाली बीमारियों को जन्म दे रही है।

विगत वर्षों में इसके पानी के विषाक्त होने के कारण करीब 300 मौतें हो चुकी हैं। ऐसी भयावह स्थिति अन्य नदियों की न हो, इसके लिए नदियों को बचाने के दिशा में सबको आगे आना होगा। यह काम सिर्फ सरकार, एक व्यक्ति या किसी एक संस्था से संभव भी नहीं है।

बालाजी डेंटल केयर

Address
Shiv Bhawan,
Laah Kothi, Ratu
Road, Ranchi-5
Ph. 9006833759

PICK - UP COMPUTERS
A Complete Solution of Computer & Home Appliances
Our Service :- Assembled Computer, Branded Desktop & Laptop Peripherals Networking, Hardware & Software, Accessories, Projector
लीपि व अन्य कंपनियों के कांपटिबल कार्ट्रिज के के लिये संपर्क करें
C.C.T.V कैमरा के लिए सम्पर्क करें।
सबसे सस्ता सबसे बढ़िया
H.O.: HAWAI JAHAJ KOTHI, OPP. YAMAHA SHOWROOM, KANKE ROAD, RANCHI
Mob. - 9308466589, 9334729492

फोटो न्यूज

कुछ सालों से कुल्हड़ चाय का जलवा रांची में दिख रहा है। भले इसमें चाय पीने में कुछ पैसे ज्यादा लगें, पर पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनो के खयाल से ये अच्छा है। फोटो : उज्ज्वल

संदेश साफ़ है कि आप बांस की बनी चीजो को फर्नीचर में इस्तेमाल कर सकते हैं पेड़ को काटे और नुकसान किये बगैर

जेसोवा मेला में पर्यावरण पर क्या है खास

मोराबादी मैदान रांची से शशि

बांस से तरह तरह के घरेलू सामानों को बहुत करीने से महिलाएं बना रही है, तथा आपको बरबस ही उनकी इस अद्भुत मोह लेने वाली चीजे ध्यान आकृष्ट कर लेगी,इससे महिलाओं का एक समूह अपनी कला को न हीं सिर्फ बढ़ा रही है बल्कि रोजगार का साधन ढूंढ ली है.

खास स्टाल - सिपेट जो चार -R की पालिसी Reduse, Reuse, Recycle, Recover पर वेस्ट मैनेजमेंट पर कार्य करती है।तथा इसके फायदे से भी आपको अवगत कराते हुए सिपेट के कर्मचारी मिलेंगे जो बताते हैं की वेस्ट मैनेजमेंट से हमारा पर्यावरण साफ़ सुथरा रहता है ,रोजगार के साधन बढ़ते हैं ,व्यापार के अवसर होंगे इकोनोमिकल प्रोडक्ट होंगे, लो कॉस्ट सप्लाई श्रृंखला बनेगा। सबसे आकर्षण की बात ये है की वो रॉ मटेरियल जो बेकार में हम फेकते है उसका कैसे रिसायकल होता है उसकी जानकारी आपको इस स्टाल से प्राप्त होती है।

ट्राइबल फ़ूड कैफेटेरिया" स्टाल में यदि आप खाने के शौक़ीन है और झारखण्डी व्यंजन को चखना चाहते है तो आप यहाँ जाकर रसास्वादन कर सकते है। इसमें खासियत यह है की जो व्यंजन परोसे जाते है वो पते का दोना, मकई से निर्मित प्लेटें व कागज की प्लेट होती है जो पूर्णतः पर्यावरण अनुकूल हैं।

टीम ग्रीन" के स्टाल में नौजवान युवक युवतियां आपको वृक्ष संरक्षण के लिये आपकी जानकारी को बढ़ाने में मदद करते है .इसके अलावे यदि वहाँ से आप प्लांट बैग की खरीदारी करते है तो **TEAM GREEN** के सदस्य प्लांटेशन ड्राइव के तहत आपके द्वारा खरीद की हुई पर्ची के माध्यम से पौधे लगाने का भी काम करते है।

कृषि वैज्ञानिक दलहनी एवं तेलहनी फसल बीज उत्पादन पर फोकस करें

संवाददाता

रबी फसल बीज उत्पादन समीक्षा बैठक का आयोजन

रांची :बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के तहत निदेशालय बीज एवं प्रक्षेत्र द्वारा बीएयू मुख्यालय बीज प्रक्षेत्र, हजारीबाग स्थित गोरियाकर्मा बीज प्रक्षेत्र तथा सभी 16 केवीके के माध्यम से नाभकीय, प्रजनक, आधार एवं प्रमाणित बीज का उत्पादन करती है। 17 अक्टूबर को निदेशालय द्वारा कुलपति डॉ आरएस कुरील की अध्यक्षता में रबी फसल बीज उत्पादन समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। मौके पर उन्होंने बताया कि सोयाबीन फसल को बढ़ावा देकर मध्य प्रदेश खुशहाल राज्य बना। झारखण्ड में दलहनी एवं तेलहनी फसलों को बढ़ावा देने की काफी संभावना मौजूद है।

राज्य के एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को चना, सोयाबीन, सरसों, तीसी एवं तिल के बीज उत्पादन में फोकस करने की जरूरत है। इन फसलों की खेती को व्यापक पैमाने पर बढ़ावा देकर राज्य को कृषि मामले में समृद्ध एवं खुशहाल बनाया जा सकता है। कुलपति ने वैज्ञानिकों को विश्वविद्यालय द्वारा विकसित प्रभेदों के बीज उत्पादन को प्राथमिकता तथा बिरसा बीज ब्रांड के नाम ने बीज का विक्रय करने का निर्देश दिया। उन्होंने बीज उत्पादन से जुड़े प्रक्षेत्रों में बेकार पड़े भूमि के विकास के लिए ई डीके रूसिया को मार्गदर्शन हेतु अधिकृत और जेसीबी मशीन का क्रय करने पर सहमति दी। इस अवसर पर विशेषज्ञ भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर के पूर्व निदेशक डॉ शंकर लाल ने बीज के मामले में गुणवत्ता बनाये रखने, बीज जाँच एवं सत्यापन की बेहतर व्यवस्था तथा बीज उत्पादन तकनीकी पर प्रकाश डाला। निदेशक अनुसंधान डॉ डीएन सिंह ने विश्वविद्यालय द्वारा उत्पादित बीजों का राज्य सरकार द्वारा मांगपत्र देने के बावजूद क्रय एवं उठाव नहीं करने के कारण उत्पादित बीज को अन्य कृषि विश्वविद्यालयों की तरह सीधे बाजार में विक्रय करने पर जोर दिया।

निदेशक बीज एवं प्रक्षेत्र डॉ ऋषि पाल सिंह ने बताया कि रबी 2018 में विश्वविद्यालय द्वारा धान्य, दलहनी एवं तेलहनी फसलों के तहत कुल 5 मुख्य फसलों की 6 प्रभेदों का 19।25 क्विंटल प्रजनक बीज, 8 फसलों के 24 प्रभेदों का 958।83 क्विंटल आधार बीज का उत्पादन किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन तहत संचालित 5 सीड हब में विभिन्न दलहनी फसलों के 1024।5 क्विंटल आधार बीज का उत्पादन किया गया। इसके अलावा 7 हजार क्विंटल गन्ने के आधार बीज का उत्पादन किया गया। उन्होंने रबी 2019 में विभिन्न फसलों के विभिन्न प्रभेदों के 1558 क्विंटल तथा दलहन सीड हब में 1855 क्विंटल बीजोत्पादन का प्रस्ताव रखा। उन्होंने बताया कि राज्य की जरूरत का 30 प्रतिशत बीज का उत्पादन विश्वविद्यालय द्वारा की जाती है। बीज मामले में राज्य की जरूरत को पूरा करने में विश्वविद्यालय सक्षम है।डॉ सुप्रिया ने रबी 2019 की कार्य योजना तथा डॉ रवि कुमार ने राष्ट्रीय बीज परियोजना एवं डॉ एसएन गिरी ने गोरियाकर्मा बीज प्रक्षेत्र की उपलब्धियों एवं आगामी रबी बीज रणनीति प्रस्तुत की।

बैठक में सभी कृषि विज्ञान केन्द्रों एवं क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों के वैज्ञानिकों सहित डॉ एमपी सिन्हा, डॉ एमएस यादव, डॉ सुशील प्रसाद, डॉ जेडए हैदर, ई डीके रूसिया और डॉ डीके शाही ने भाग लिया।●

झारखण्ड के किसानों का इजरायल दौरा

आधुनिक खेती क्या और कैसे होती है यहां आकर जाना :तुलसी महतो, कृषक

हमें क्या पता था आधुनिक खेती कैसे और क्या होती है हम तो परंपरागत ढंग से अब तक खेती करते आ रहे थे। लेकिन सरकार ने हमें इजराइल भेज कर आधुनिक खेती की जानकारी दी। अब यहां से प्राप्त जानकारी को उपयोग में लाऊंगा। साथ ही अपने कृषक मित्रों को भी इन पद्धतियों को अपनाने की सलाह दूंगा। ताकि वे कम पानी में अधिक उत्पादन कर अपना आर्थिक स्तर ऊंचा कर सकें। यह कहना है खूंटी के कृषक तुलसी महतो का जो पाकुड़ के उपायुक्त कुलदीप चौधरी के नेतृत्व में 24 सदस्यीय किसानों के दल के साथ इजराइल दौरे पर हैं।

किसानों ने देखी कैसे होती है नारंगी की खेती पाकुड़ उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने बताया को दौरे के तीसरे दिन सिट्रस के खेत का दौरा किया। किसान जैकब शेमेश अपने खेत में विभिन्न प्रकार के नारंगी समेत अन्य खट्टे फलों का उत्पादन कर रहें हैं। वे नारंगी के ओआरआई, नई होली और मैंडरेन विकसित कर मुनाफा कमा रहें हैं। वे 20 हेक्टेयर क्षेत्र में उत्पादन कर प्रति हेक्टेयर 20 हजार डॉलर शुद्ध लाभ प्राप्त कर रहें हैं। इसके बाद दल जैकब शेमेश की फसल पैकेजिंग यूनिट का दौरा किया। किसानों ने वहां खट्टे फलों की पैकेजिंग की प्रक्रिया को देखा। फलों की सफाई, शॉर्टिंग, वैक्सिंग, ग्रेडिंग और पैकेजिंग इस यूनिट में की जाती है। अनार के खेत भी गए किसान

नारंगी के खेत देखने के बाद किसानों ने लिहू नामक किसान के खेत का दौरा किया। लिहू 25 हेक्टेयर भूमि पर अनार की खेती कर रहें हैं। किसानों ने खुबानी और सतालू की खेती की प्रक्रिया भी देखी।

सूरज से निकलेगा तरक्की का नया रास्ता

स्वामीनाथन एस. अय्यर

सरकार का कहना है कि जम्मू-कश्मीर को केंद्रशासित प्रदेश बनाने से वहां औद्योगिक निवेश की लहर आएगी, आर्थिक वृद्धि की रफ्तार बढ़ेगी और काफी रोजगार पैदा होंगे। अभी तो यह कल्पना ही है। अलबत्ता बिना किसी हंगामे के इधर 45 हजार करोड़ की एक विशाल परियोजना जरूर शुरू हो रही है, जिसका ठिकाना जम्मू या कश्मीर घाटी न होकर लद्दाख है। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की पहल पर आई इस परियोजना का लक्ष्य सन 2023 तक 7500 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करना है। लद्दाख का ठंडा रेगिस्तान भारत में और किसी भी स्थान की तुलना में ज्यादा सौर ऊर्जा प्राप्त करता है। इसका कारण है बिना बादलों वाले यहां के दिन और साफ पहाड़ी आसमान।

अनुकूल मौसम

वर्षा की दृष्टि से लद्दाख हिमालय की छाया में पड़ता है लिहाजा मॉनसून में यहां बारिश बहुत कम होती है। जाड़ों में पछुआ हवाओं के साथ यहां कुछ बर्फबारी जरूर हो जाती है लेकिन बादल यहां नहीं के बराबर ही घिरते हैं। यही वजह है कि सूरज की ऊर्जा को

बिजली में बदलने की दर यहां भारत भर में सबसे ऊंची है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि देश के दूसरे नंबर के सोलर स्थल राजस्थान की तुलना में लद्दाख से प्रति सोलर सेल 10 प्रतिशत ज्यादा बिजली प्राप्त की जा सकती है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह के मुताबिक लद्दाख में 23 हजार मेगावाट सौर ऊर्जा की संभावना मौजूद है, लिहाजा अगर यहां 7500 मेगावाट की पहली परियोजना कामयाब रहती है तो बाद में इसकी क्षमता बढ़ाकर तीन गुनी की जा सकती है। इसके अलावा पवन ऊर्जा को तो अभी इसमें शामिल ही नहीं किया गया है। लद्दाख में हवा की रफ्तार बहुत ज्यादा होती है। सोलर फार्मों के आसपास विंड टर्बाइनें लगाना समझदारी का काम होगा। सौर ऊर्जा को ले जाने के लिए बनाई गई ट्रांसमिशन लाइनें पवन ऊर्जा ले जाने में भी काम आ सकती हैं। आरके सिंह पिछले कुछ समय से इस परियोजना को आगे बढ़ाने में जुटे हैं। यह दो भागों में है। 2,500 मेगावाट का एक हिस्सा सुरू और जांस्कर में है, जहां से ट्रांसमिशन लाइन के जरिए कश्मीर घाटी में बिजली पहुंचाई जाएगी। दूसरा हिस्सा 5,000 मेगावाट का है (भावी परियोजनाएं जोड़कर) जिससे जुड़ी ट्रांसमिशन लाइन दक्षिण में हरियाणा और दिल्ली की जरूरतें पूरी करेगी। सोलर पावर के लिए बड़े पैमाने पर जमीन की जरूरत पड़ती है। कई राज्यों में जमीन की ऊंची कीमत ने सौर ऊर्जा के विस्तार को बाधित किया है। लेकिन लद्दाख में जमीन काफी सस्ती है। खुद सरकार के पास वहां काफी जमीन है। चरागाह की अधिगृहीत भूमि के लिए विभिन्न समुदायों को 1200 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सालाना भुगतान किया जाएगा, जिसमें 3 फीसदी की वार्षिक वृद्धि होती रहेगी।

इस तरह ग्रामीणों को चराई से जितना मिलता है उससे काफी ज्यादा राशि मिल जाएगी और जमीन पर खर्च कम आने से बिजली की लागत भी कम हो जाएगी। लेकिन अफसोस कि बाकी मामलों में लद्दाख के लिए यह लागत भारत के केंद्रीय इलाकों की तुलना में काफी ज्यादा पड़ेगी। पानी वहां बहुत कम है और सड़कें भी। अभी सौर ऊर्जा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए काफी सारी सड़कें बनानी पड़ेंगी। बिजली का ढांचा बहुत कमजोर है इसलिए डीजल से चलने वाले जेनरेटरों का प्रयोग शुरू में लगभग हर जगह करना होगा। लद्दाख के छोटे-छोटे गांवों में जनसंख्या और कौशल भी कम है इसलिए देश के भीतरी इलाकों से ऊंची मजदूरी पर कामगार लाने होंगे। परियोजना स्थलों पर उपकरण बहुत दूर से पहुंचाने होंगे। रोहतांग दर्रे के भीतर से एक नई 8.8 किमी की सुरंग का निर्माण पूरा होने को है जिससे मनाली से लद्दाख पहुंचाना आसान हो जाएगा। संयंत्र लगाने में कई तरह की समस्याएं आएंगी। मिट्टी भुरभुरी है, जिसे सख्ती से जमाना होगा। ऊंची जगहों पर होने वाली दिक्कतें 10,000 फीट की ऊंचाई पर काम कर रहे मजदूरों को प्रभावित कर सकती हैं। शून्य से नीचे तापमान और तेज हवाओं के बीच निर्माण कार्य काफी चुनौतीपूर्ण होगा।इसलिए विश्लेषकों को आशंका है कि लद्दाख प्रॉजेक्ट के लिए बोली 5 रुपये प्रति यूनिट से ऊपर जाएगी, जो मैदानी इलाकों के मुकाबले दोगुना है। लद्दाख ऊर्जा तो ढेर सारी दे सकता है, पर ऊंची लागत पर। बेशक, इससे लद्दाखी युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर बनेंगे, लेकिन कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस से जुड़े हाई स्किल कामों की जरूरत बाहरी युवा ही पूरी कर पाएंगे।

विधानसभा चुनावों की तैयारी के लिये हुई बैठक

संवाददाता

रांची :आगामी झारखंड विधानसभा निर्वाचन के आलोक में निर्वाचन व्यय पर्यवेक्षण एवं इंफोर्समेंट से संबंधित विभागों के नोडल पदाधिकारियों के साथ सुदीप जैन उप निर्वाचन आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग एवं अरविंद आनंद सचिव भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बैठक की गई। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान नकदी की आवाजाही, निर्वाचन व्यय की मॉनिटरिंग, मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए शराब, उपहार आदि की आवाजाही पर निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाय। स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने में निर्वाचन व्यय पर्यवेक्षण एवं इनफोर्समेन्ट से संबंधित विभागों से तत्पर सहयोग जरूरी है। बैठक में विनय कुमार चौबे, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, कृपानंद झा , अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मुरारी लाल मीणा व अन्य उपस्थित थे।

अखबार के स्वामी सन कम्युनिकेशन के लिये प्रकाशक मनोरंजन सिंह द्वारा प्रकाशित तथा मेसर्स डी. बी. कॉर्प लिमिटेड,प्लॉट नं535 एवं 1272 ललगुटवा पुलिस स्टेशन, रातू, रांची (झारखंड) से मुद्रित और सन कम्युनिकेशन,अपोजिट कब्रिस्तान गेट नं.-2, टीवीएस गली, रातू रोड, रांची-834001 (झारखंड) से प्रकाशित। संपादकः मनोज कुमार शर्मा* (पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिये उत्तरदायी)आर.एन.आइ. पंजीयन क्रमांक : JHAHIN00962, email:greenrevolt2019@gmail.com. Ph. 8539978825, 8825374626. समस्त विवाद रांची न्यायालय के अधीन होंगे।